प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
01.01.2026 / प्रादेशिक समाचार / 18.00बजे

प्रश्नकाल
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद ओबीसी आरक्षण पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन किया गया है और आयोग भी इस विषय पर मंथन कर रहा है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग का कल्याण राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि उनके हित के लिए करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अलग–अलग क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था है और जातीय जनगणना के बाद कई तथ्य सामने आएंगे। सरकार की ओर से विधानसभा में दिए गए लिखित जवाब के अनुसार प्रदेश में सरकारी विभागों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर ओबीसी को वर्ग–ए और बी में 12 प्रतिशत जबकि वर्ग–सी व डी में 18 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। सरकारी विभागों में प्रशिक्षण के लिए भी अलग–अलग संस्थानों और पाठ्यक्रमों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्बाल के मूल सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते तीन वर्षों में 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश के विभिन्न विभागों के 2 हज़ार 35 संस्थान बंद किए गए, जबकि 3 सौ 62 नए संस्थान खोले गए। उन्होंने बताया कि बंद किए गए संस्थानों में से एक सौ 23 को बाद में फिर से शुरू किया गया। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सरकार संस्थानों को राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि जनता की जरूरत और आकलन के आधार पर खोल रही है। उन्होंने कहा कि संस्थानों को बंद करना सरकार का नीतिगत फैसला होता है और यह व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लिया जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में संस्थान खोले और कई स्वास्थ्य संस्थान भी खोले गए, लेकिन वहां डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गुणवत्ता, आधारभूत ढांचे और जनता की जरूरत को ध्यान में रखकर संस्थान खोल रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के जवाब पर सवाल उठाया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के अगले ही दिन यह कैसे तय हो गया कि भाजपा सरकार के समय खोले गए संस्थान जरूरत के आधार पर नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कई संस्थान राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से बंद किए गए।

जयराम ठाकुर
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर विधानसभा में सवालों के तथ्यात्मक जवाब न देने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में जवाब देने के बजाए जनसभा की तरह भाषण देते हैं, जिससे सदन की गरीमा को ठेस पहुंच रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद मौजूदा सरकार के पांच साल के सभी फैसलों की समीक्षा होगी और जो फैसले जनहित में नही होंगे उन्हें रद्द किया जाएगा।

जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार कर्मचारी हितैषी है तो पैंशनरों को अपने हक के लिए धरने पर क्यों बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के चार साल के कार्यकाल में प्रदेश में विकास थम गया है और पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही हिम–चंडीगढ़ सिटी का विकास कार्य शुरू करेगी। शिमला में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने चंडीगढ़ के निकट बद्दी क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताओं के कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में तीन नए शहर और सिरसा रिवर फ्रंट विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि ये नए शहर लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे और प्रदेश का राजस्व भी बढ़ाएंगे।

जनगणना

प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना के दूसरे चरण का कार्य आज से शुरू हो गया है, जो 30 सितंबर तक संचालित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान प्रगणक घर–घर जाकर जनसंख्या गणना से संबंधित आंकड़े एकत्रित करेंगे। जनगणना विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस चरण में प्रदेश के पूर्ण व आंशिक बर्फबारी वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

ब्लास्टिंग

लाहौल स्पीति जिले में राशेल–लिंगर सड़क निर्माण कार्य के दौरान की जा रही ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीण चिंतित हैं। स्थानीय लोगों ने जिला उपायुक्त और लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता को लिखित शिकायत के माध्यम से निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए जा रहे विस्फोटकों और उससे होने वाले नुकसान की जांच करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लास्टिंग के बाद गांव के कुछ घरों की दीवारों में दरारें आई हैं। ऐसे में सड़क निर्माण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

————————————————————————————————————